IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सतत विकास लक्ष्यों को आकार देने में नारीवादी नागरिक समाजिक संगठनों के लिए चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

प्रो0 गोपाल प्रसाद[1], सत्यपाल यादव[2], डॉ0 समरेन्द्र बहादुर शर्मा[3]

प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सहयुक्त आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, बी0 आर0 डी0 पी0 जी0 कालेज, देवरिया

सारांश

यह शोध पत्र सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के कार्यान्वयन को आकार देने में नारीवादी नागरिक समाज संगठनों एफसीएसओ के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों की जांच करता है। क्षेत्र देश में जनसंख्याए एफसीएसओ के गुणात्मक अध्ययन के माध्यम से हम प्रमुख बाधाओं की पहचान करते हैं सीमित संसाधनोंए राजनीतिक विरोध और प्रतिस्पर्धी हितों सहित, इन चुनौतियों के बावजूद हम एफसीएसओ के लिए एसडीजी कार्यान्वयन को प्रभावित करने के अवसर भी पाते हैं, जिसमें सरकारों को जवाबदेह बनाने, समुदायों को संगठित करने और लिंग-परिवर्तनकारी नीतियों को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका शामिल है एसडीजी के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में एफसीएसओ की भूमिका, और उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए बढ़े हुए समर्थन और संसाधनों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, यह शोध पत्र नागरिक समाज, लिंग और सतत विकास पर साहित्य में योगदान देता है- और नीति और अभ्यास के बारे में जानकारी देता है एसडीजी हासिल करने में।

मुख्य शब्द - सतत विकास लक्ष्य, नारीवादी नागरिक सामाजिक संगठन, एफ0सी0एस0ओ0, सामाजिक न्याय, प्रतिस्पर्धी हित, निर्णय प्रक्रिया, लैंगिक समानता

प्रस्तावना

2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी का लक्ष्य 2030 तक एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया को बढ़ावा देना है। नारीवादी नागरिक समाज संगठन, एफसीएसओ इन लक्ष्यों को आकार देने में सहायक रहे हैं, विशेष रूप से लैंगिक समानता और महिलाओं से संबंधित हालाँकि एफसीएसओ को एसडीजी कार्यान्वयन को प्रभावित करने के अपने प्रयासों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सीमित संसाधन, राजनीतिक विरोध और प्रतिस्पर्धी हित शामिल हैं। इन चुनौतियों के बावजूद एफसीएसओ के पास एसडीजी कार्यान्वयन को आकार देने और यह सुनिश्चित करने के अवसर हैं कि लक्ष्य इस तरह से हासिल किए जाएं जिससे लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। यह शोध पत्र विशिष्ट क्षेत्र या देश पर ध्यान केंद्रित करते हुए

एसडीजी कार्यान्वयन को आकार देने में एफसीएसओ के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पड़ताल करता है। इस संदर्भ में एफसीएसओ के अनुभवों की जांच करके इस शोध का उद्देश्य एसडीजी प्राप्त करने और अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत दुनिया को बढ़ावा देने में नागरिक समाज की भूमिका की गहरी समझ में योगदान करना है।

नारीवादी नागरिक समाज लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक समझौतों का लाभः-

नारीवादी नागरिक समाज लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक समझौतों का लाभ उठा सकता है, इसके लिए वह लैंगिक समानता का समर्थन और प्रचार करने वाले विभिन्न उपकरणों और प्लेटफार्मों का उपयोग कर सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख रणनीतियाँ और अवसर दिए गए हैं-

वैश्विक समझौतों और प्लेटफार्मो का लाभ उठाएं-

1. नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता लैंगिक समानता उपकरण- नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता लैंगिक समानता उपकरण नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रोग्रामिंग को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें नीतिगत ढाँचे, भागीदारों को शामिल करना, लिंग-आधारित विश्लेषण और लैंगिक समानता परिणामों पर प्रदर्शन की निगरानी के लिए उपकरण शामिल हैं।
2. शिक्षा मे और उसके माध्यम से लैंगिक समानता और लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वैश्विक मंच- यह मंच एक बहु-हितधारक मंच है जिसमें सरकारी प्रतिनिधि, नेता, भागीदार और कार्यकर्ता शामिल हैं। यह शिक्षा में लैंगिक समानता को संबोधित करने के लिए जवाबदेही, कार्रवाई और सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मंच वैश्विक जवाबदेही डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति की निगरानी करता है और उच्च-प्रभाव समाधानों पर साक्ष्य साझा करता है।
3. यूएन महिला नागरिक समाज भागीदारी- यूएन महिला अंतर-सरकारी प्रक्रियाओं में नागरिक समाज की भागीदारी का समर्थन करती है, जैसे कि महिलाओं की स्थिति पर आयोग। इस भागीदारी का उद्देश्य राजनीतिक एकजुटता और नारीवादी आंदोलन निर्माण को मजबूत करना है, यह सुनिश्चित करना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाज सुनी जाए।
4. महिला अधिकारों और लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय साधन-महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन BPFA जैसे साधन लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं। नागरिक समाज सरकारों को जवाबदेह ठहराने और लिंग.संवेदनशील नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत करने के लिए इन साधनों का लाभ उठा सकता है।
5. महिला अधिकारों और लैंगिक समानता पर ऑक्सफैम रिपोर्ट- यह रिपोर्ट लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों CSO पर बदलते सहायता वातावरण के प्रभाव की पड़ताल करती है। यह CSO को नीतियों और कानून को प्रभावित करने में सक्षम बनाने में दाता समर्थन के महत्व पर प्रकाश डालता है, हालाँकि नीतियों और व्यवहार के बीच का अंतर महत्वपूर्ण बना हुआ है।

नारीवादी नागरिक समाज के लिए रणनीतियाँ-

1. वकालत और नीतिगत प्रभाव- नारीवादी नागरिक समाज सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़कर लिंग-संवेदनशील नीतियों और कानून की वकालत कर सकता है। इसमें वैश्विक प्लेटफॉर्म में भाग लेना और नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता लिंग समानता उपकरण जैसे उपकरणों का उपयोग करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिंग समानता सभी विकास नीतियों और परियोजनाओं में एकीकृत है।
2. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण- नागरिक समाज संगठन कानून प्रवर्तन अधिकारियों और सार्वजनिक अधिकारियों सहित हितधारकों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। इसमें लिंग-संवेदनशील मानवाधिकार शिक्षा और लिंग-आधारित हिंसा की रोकथाम पर प्रशिक्षण शामिल है।
3. निगरानी और जवाबदेही- नारीवादी नागरिक समाज लिंग समानता परिणामों पर प्रगति की निगरानी कर सकता है और सरकारों को उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह ठहरा सकता है। इसमें कार्रवाई को ट्रैक करने

और सेवा प्रावधान और वित्त में अंतराल की पहचान करने के लिए लैंगिक समानता के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शामिल है।

4. दक्षिण–दक्षिण सीखना और साझा करना– नागरिक समाज संगठन दक्षिण–दक्षिण सीखने और साझा करने को बढ़ावा दे सकते हैं, जो प्रभावी प्रथाओं और समाधानों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण लिंग संवेदनशील और समावेशी कानूनों और नीतियों के विकास का समर्थन करता है।
5. भागीदारी और सहयोग– नारीवादी नागरिक समाज सरकारों, दाताओं और अन्य नागरिक समाज संगठनों सहित अन्य हितधारकों के साथ सहयोग कर सकता है, ताकि उनके प्रभाव को बढ़ाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लैंगिक समानता सभी विकास प्रयासों का एक केंद्रीय पहलू है।

चुनौतियाँ-

1. एकल नीति निर्माण– एसडीजी की परस्पर संबद्ध प्रकृति के बावजूद, चर्चाएँ, योजनाएँ और कार्यान्वयन अक्सर पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास पर केंद्रित होते हैं, जो नारीवादी शांति, निरस्त्रीकरण और लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं। नारीवादी प्राथमिकताएँ जैसे कि अंतर्संबंध, मानवाधिकार और जलवायु न्याय अक्सर मुख्यधारा के विकास चर्चाओं से बाहर रखे जाते हैं।
2. कमजोर महिला नीति एजेंसियां और लैंगिक मुख्यधारा– कई देशों में कमजोर महिला नीति एजेंसियाँ हैं, और लैंगिक मुख्यधारा को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है, जिससे लैंगिक समानता पर सीमित प्रभाव पड़ता है। बहुआयामी गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए मजबूत प्रभावी उपायों की जरूरत है, जो कि वास्तविकताओं की दृश्यता और लैंगिक न्याय पर त्वरित कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण हैं।
3. आँकड़े और निगरानी उपायों की कमी– लैंगिक समानता के लिए डेटा और निगरानी उपायों की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिससे प्रगति को ट्रैक करना और सरकारों को जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक और तकनीकी शासन में लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के विचारों के साथ–साथ सुसंगत विदेशी और घरेलू कानून के व्यवस्थित एकीकरण की आवश्यकता है।
4. संरचनात्मक बाधाएं और क्षमता अंतराल– संरचनात्मक बाधाएँए क्षमता अंतराल, भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और रूढ़ियाँ निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी को प्रतिबंधित करती हैं, विशेष रूप से छोटे द्वीप विकासशील राज्यों एसआईडीएस में। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एसआईडीएस को संरचनात्मक बाधाओं और क्षमता अंतराल को संबोधित करना चाहिए।
5. जवाबदेही और वित्तपोषण – मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना और कोर, दीर्घकालिक और लचीले वित्तपोषण के माध्यम से नारीवादी आंदोलनों को वित्तपोषित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए परिवर्तनकारी वित्तपोषण पर अदीस अबाबा कार्य योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

संभावनाएँ-

1. अंतर्विषयकता और मानवाधिकार– अंतर्विषयकता नस्ल, लिंग पहचान, आयु, विकलांगता, यौन अभिविन्यास, राष्ट्रीयता और प्रवासी स्थिति सहित संरचनात्मक असमानताओं की विशिष्टताओं और जटिल प्रकृति को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानवाधिकारों की केंद्रीयता और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही की आवश्यकता नारीवादी नागरिक समाज के सदस्यों के लिए आवश्यक है।
2. लैंगिक मुख्यधारा और महिला नीति एजेंसियाँ– मजबूत महिला नीति एजेंसियाँ और प्रभावी लिंग मुख्यधाराकरण नए लिंग समानता कानून बना सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकते हैं। चिली जैसे देशों ने नए लिंग समानता कानून बनाने में मजबूत महिला नीति एजेंसियों की क्षमता का प्रदर्शन किया है।
3. नारीवादी रणनीतियाँ और नागरिक समाज जुड़ाव– एसडीजी को लागू करने के लिए नारीवादी रणनीतियों में सैन्यवाद, पितृसत्ता और पूंजीवाद जैसी उत्पीड़न प्रणालियों को खत्म करना और नागरिक समाज के स्थान को बढ़ाना और उसकी रक्षा करना शामिल है। नीति विकास और कार्यान्वयन के लिए नागरिक समाज की भागीदारी

महत्वपूर्ण है, जैसा कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में महिला समूहों की भूमिका में देखा गया है।

4. लिंग संवेदनशील और समावेसी कानून और रणनीतियाँ– एसआईडीएस को लिंग–संवेदनशील और समावेशी कानूनों, नीतियों, रणनीतियों और योजनाओं के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए जो लिंग समानता और महिलाओं के मानवाधिकारों को प्राथमिकता देते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तन्यकता निर्माण में लिंग समानता और महिलाओं के नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए UNFCCC सेंडाई फ्रेमवर्क और अन्य जलवायु और जैव विविधता समझौतों के लिए लिंग कार्य योजनाओं GAPs को लागू करना आवश्यक है।
5. लैंगिक आँकड़े एकत्र करना और उसका उपयोग करना– महिलाओं पर आपदाओं के विभेद प्रभावों को समझने और नीति और कार्यक्रम विकास को सूचित करने के लिए लैंगिक आँकड़े एकत्र करना और उसका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तन्यकता निर्माण में महिलाओं को शामिल किया जाए, लिंग–संवेदनशील और समावेशी प्रारंभिक चेतावनी संदेश और प्रणालियाँ आवश्यक हैं।

निष्कर्ष-

1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी। हालाँकि, पिछले 25 वर्षों में सतत विकास के क्षेत्र ने कार्य आधारित नीतियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और समानता को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं की है। यह शोध पत्र यह समझने में पहला कदम प्रदान करता है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेने वाले प्रतिभागी महिला नेताओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को क्या मानते हैं। नारीवादी नागरिक समाज के सदस्यों को सतत विकास लक्ष्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एकाकी नीति निर्माण, महिलाओं की नीति एजेंसियों की कमजोरी, आंकड़े और निगरानी उपायों की कमी और महिलाओं की भागीदारी में संरचनात्मक बाधाएँ शामिल हैं। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सतत विकास लक्ष्यों को महिलाओं और हाशिए पर पड़ी आबादी के लाभ के लिए लागू किया जाए, अंतर्संबंध, मानवाधिकार और नारीवादी रणनीतियों का लाभ उठाने के अवसर मौजूद हैं। सतत विकास लक्ष्यों के ढांचे के भीतर लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रभावी जुड़ाव महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अंतर्विभागीयता, पहचान की राजनीति, और रंगीन महिलाओं के खिलाफ हिंसा, स्टैनफोर्ड लॉ रिव्यू, 43(6), 1241-1299
2. जवाद, एच., (2009), अरब जगत में महिला सशक्तिकरण पर राजनीतिक इस्लाम का प्रभाव, जर्नल ऑफ वीमेन, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी, 30(1), 1-22
3. कबीर, एन., (2005), लिंग, गरीबी और ग्रामीण एशिया में बाज़ार संबंधों का प्रसार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
4. क्लासेन, एस., (2002), लड़कियों के लिए कम स्कूली शिक्षा, सभी के लिए धीमी वृद्धि? क्रॉस–कंट्री साक्ष्य. विश्व बैंक आर्थिक समीक्षा, 16(3), 345-373
5. मोलिनेक्स, एम., (2002), लिंग और सामाजिक पूंजी की खामोशियाँ: लैटिन अमेरिका से सबक, विकास और परिवर्तन, 33(2), 167-188.
6. पटेल, आर., (2014), लिंग, कामुकता और एमडीजी: साक्ष्य की एक महत्वपूर्ण समीक्षा, जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, 26(5), 548-562
7. सैंडलर, जे., (2014), लिंग, गरीबी और ग्रामीण एशिया में बाज़ार संबंधों का प्रसार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
8. सेन, ए., (1999), स्वतंत्रता के रूप में विकास. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
9. https://www.feministpolicyindia.org/documents/resources/Suneeta%20Dhar-3.pdf
10. https://www.wilpf.org/feminist-strategies-for-implementing-the-sustainable-development-goals/
11. https://www.sdg16hub.org/system/files/2020-08/WILPF_WPS-SDGs-Guide_Web.pdf
12. https://sdg-action.org/looking-to-the-sun-pushing-forward-for-gender-equality/
13. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23808EGMViennaFin.pdf